



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY,

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 522]
No. 522]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 1986/कार्तिक 16, 1908
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 1986/KARTIKA 16, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1986

अधिसूचना

सा.का.नि. 1194(अ).—उच्च न्यायालय न्यायाधीश (मेधा शर्त)
अधिनियम, 1954 (1954 का 28) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उच्च न्यायालय न्यायाधीश
याथा भत्ता नियम, 1956 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्न-
लिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. (1) ये नियम उच्च न्यायालय न्यायाधीश याथा भत्ता (संशोधन)
नियम, 1976 कहलायेंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से
प्रवृत्त होंगे।

2. उच्च न्यायालय न्यायाधीश याथा भत्ता नियम, 1956 में,

(1) नियम 3—क में, उप नियम (ख) के बाद निम्नलिखित उप
नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

“(ग) “मीन भत्ता” का तात्पर्य संबंधित निदेशक, परिवहन द्वारा
सूचित टैक्सी/प्रायोजिका के भाड़े की दर से मार्ग का मील
में दूरी के अनुसार भत्ता।”

(2) नियम 2, उपनियम (1) में—

(i) खंड (ग) में,—“32 पैसे प्रति किलोमीटर” कोष्ठक में दिखाये
गये, शब्द तथा संख्या के स्थान पर “संबंधित निदेशक, परिवहन
द्वारा सूचित प्रायोजिका के प्रति किलोमीटर के भाड़े की
दर का आधा” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) खंड (घ) में,—“1.30 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भत्ता”
संख्या तथा शब्दों के स्थान पर संबंधित निदेशक परिवहन द्वारा
सूचित मील में भत्ता” शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे;

(iii) खंड (ङ) में (क) “35 रुपये” शब्द तथा संख्या के स्थान
पर “100 रुपये” शब्द तथा संख्या प्रतिस्थापित किए जायेंगे,

(ख) दूसरे पर्वतुक में—

(1) वर्तमान पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित
किया जाएगा, अर्थात्—

(1) जब किसी न्यायाधीश से अपनी सामान्य इपूटी के मुख्यालय
से बाहर किसी दूसरे स्थान में इपूटी करने की आवश्यकता
हो, वगैरह कि राष्ट्रपति प्रत्येक मामले में ऐसी स्थिति निर्धारित
करें, तो सभी स्थानों में भत्ता स्वीकृत किया जाएगा जो
100 रुपये प्रतिदिन से अधिक न हो और बर्रह, कवकना,
मद्रास, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद और बनगोर जैसे विशेष
स्थानों अथवा प्रायोजिका द्वारा घोषित ऐसे स्थानों
में परिवहन व्यय जो 20 रुपये प्रतिदिन से अधिक न हो

स्वीकृत किया जाएगा और सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली ममान दरों पर सरकारी आवास के लिए भी प्राप्त होगा,

- (ii) पैरा (ii) में "42 रुपये" शब्द और संख्या के स्थान पर "100 रुपये" शब्द और संख्या प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) पैरा (iii) में "25 रुपये" शब्द तथा संख्या के स्थान पर "100 रुपये" शब्द और संख्या प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(3) नियम 6, उपनियम (ख) में निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) जब मजक से यात्रा कर रहे हों:—

- (i) स्वयं न्यायाधीश के लिए एक मील भत्ता,
- (ii) यदि उनके साथ उसके परिवार के दो सदस्य यात्रा कर रहे हों तो स्वयं उस पर लागू दर पर एक अनिश्चित मील भत्ता, और यदि उनके साथ दो सदस्यों से अधिक यात्रा कर रहे हों तो उससे दोगुनी दर से मील भत्ता देय होगा।
- वर्षों कि यदि यात्रा का कोई भाग रेल द्वारा पूरा किया जा सकता है तो यात्रा के उस भाग के लिए जिसके लिए भत्ते का दावा किया गया है यह भत्ता उस यात्रा राशि से अधिक नहीं होगा, यदि न्यायाधीश और उनके परिवार के सदस्य ने ऐसे भाग की यात्रा रेल द्वारा सबसे उंची श्रेणी में की हो जिसमें वातानुकूलित श्रेणी भी शामिल है";

(4) नियम 7-क के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"7-क नियम 5 में किसी बात के होते हुए भी, उच्च न्यायालय न्यायाधीश, जिस राज्य में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ स्थित हो उस राज्य सरकार के सचिव के रैंक वाले किसी भारतीय प्रशासन सेवा के सदस्य पर इस निमित्त लागू होने वाले नियमों के अनुसार अपनी छुट्टी के दौरान, वर्ष में दो बार, भारत के किसी स्थान का भ्रमण करने के लिए (जिसमें उसके मूल राज्य में उसका स्थायी निवास भी शामिल है) स्वयं के लिए, अपनी पत्नी तथा अपने परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत पाने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण:—

इस नियम के प्रयोजन के लिए "छुट्टी" में अवकाश भी शामिल होगा।

वर्षों कि इस नियम के अधीन दिल्ली के उच्च न्यायालय और पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, भारत सरकार के संयुक्त सचिव पद के भारतीय प्रशासन सेवा के सदस्य पर इस निमित्त लागू होने वाले नियमों के अनुसार वर्ष में दो बार भारत के किसी स्थान (इसमें मूल गृह स्थान शामिल हैं) की छुट्टी यात्रा रियायत पाने का हकदार होगा।

वर्षों कि न्यायाधीश और उसकी पत्नी को विमान से यात्रा करने या रेल से यात्रा करते समय वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का विकल्प होगा। जब न्यायाधीश या उसकी पत्नी छुट्टी यात्रा रियायत कर रहे हों तो परिवार के आश्रित सदस्यों को भी उनमें से किसी के भी साथ विमान से या वातानुकूलित प्रथम श्रेणी से यात्रा करने की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण—1:— इस नियम और नियम-7ख तथा 7-ग के प्रयोजन के लिए

"मूल राज्य में स्थायी निवास" का तात्पर्य—

(i) एक ऐसे व्यक्ति के मामले में जो भारतीय क्षेत्र में किसी स्थान पर व्यापिक पद पर हो, वह स्थान उसकी सेवा पंजी में ऐसा

स्थान रिकार्ड किया गया हो जहाँ उसका स्थायी निवास स्थित हो, और

(ii) किसी अन्य मामले में उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 1966 के प्रवृत्त होने से पहले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा घोषित वह स्थान जहाँ उसका स्थायी निवास स्थित है, या जहाँ ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है ऐसे स्थान के बारे में उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 1966 के प्रवृत्त होने से एक वर्ष के अंदर या उसकी नियुक्ति की तिथि से, जो भी बाद में हो, वह स्थान घोषित करना है जहाँ पर उसका स्थायी निवास स्थित है और इस प्रकार की गई घोषणा का तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार मामले की अपवाद स्वरूप परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसे परिवर्तन की अनुमति नहीं देती:—

वर्षों कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे परिवर्तन के लिए एक आग्रह से अधिक अनुमति नहीं दी जाएगी।

II. "वर्ष" का तात्पर्य "कलेंडर वर्ष" से है, भले ही वापसी यात्रा भ्रमण कलेंडर वर्ष में पड़ने की स्थिति में ऐसी यात्रा को उस वर्ष में किया गया समझा जाएगा जिस वर्ष में वह यात्रा प्रारम्भ की गई थी;

(5) नियम 7—ग, उप नियम (1) खंड (ख) में वर्तमान उपखंड (1) को निम्नलिखित उस खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(1) परिवार के एक सदस्य के लिए एक मील भत्ता यदि परिवार के दो सदस्य यात्रा करें तो दूसरा मील भत्ता और यदि मृतक न्यायाधीश के परिवार के दो से अधिक सदस्य यात्रा करें तो तीसरा मील भत्ता अंतिम इयूटी तारीख को न्यायाधीश को मिलने वाली दर पर दिया जाएगा।

(6) नियम 7-घ उप नियम (ख) में वर्तमान उप खंड (i) और (ii) की निम्नलिखित उप खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"न्यायाधीश के लिए एक मील भत्ता यदि उनके साथ उनके परिवार के दो सदस्य यात्रा कर रहे हों तो दूसरा मील भत्ता और यदि उनके साथ उनके परिवार के दो से अधिक सदस्य यात्रा कर रहे हों तो तीसरा मील भत्ता—अंतिम इयूटी तारीख को न्यायाधीश को मिलने वाली दर पर दिया जाएगा।"

(7) नियम 7-ख और 7-ड का लोप किया जाएगा.

(8) नियम 7-ग और 7-घ को बदल कर क्रमशः 7-ख और 7-ग किया जाएगा।

[24/19/86—न्याय]

जे एस. बघन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:—मूल नियम अधिसूचना सं. का. नि. भा. 2401, तारीख 23 अक्टूबर, 1956 के साथ भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, तारीख 27 अक्टूबर 1956 पृष्ठ 1762 पर प्रकाशित किए गए थे—तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:—

- (1) का. नि. भा. 708, तारीख 28-2-1957
- (2) सा. का. नि. 48, तारीख 9-1-1959
- (3) सा. का. नि. 730, तारीख 4-5-1965
- (4) सा. का. नि. 943, तारीख 8-6-1966
- (5) सा. का. नि. 1768, तारीख 18-9-1968
- (6) सा. का. नि. 891, तारीख 19-3-1969
- (7) सा. का. नि. 784, तारीख 2-5-1970
- (8) सा. का. नि. 1539, तारीख 4-9-1971

- (9) सा. का. नि. 841 तारीख 21-6-1972
 (10) सा. का. नि. 344 (प्र) तारीख 12-5-1976
 (11) सा. का. नि. 991, तारीख 28-7-1978
 (12) सा. का. नि. 502, तारीख 23-3-1979
 (13) सा. का. नि. 870, तारीख 5-8-1980
 (14) सा. का. नि. 1044, तारीख 21-9-1980
 (15) सा. का. नि. 360, तारीख 10-3-1981
 (16) सा. का. नि. 532, तारीख 27-5-1982
 (17) सा. का. नि. 887 तारीख 15-10-1982
 (18) सा. का. नि. 1007 तारीख 2-11-1985

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 7th November, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 1194(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the High Court Judges Travelling Allowance Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the High Court Judges Travelling Allowance (Amendment) Rules, 1986.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the High Court Judges Travelling Allowance Rules, 1956 :—
 - (1) In rule 1A, after sub-rule (b), the following sub-rule shall be inserted, namely :—
 - (C) "mileage allowance" means the road mileage allowance at the rate notified by the concerned Director of Transport for Taxi/Autorickshaw;"
 - (2) in rule 2, in sub-rule (1),—
 - (i) in clause (C), for the words and figures "32 paise per kilometre" appearing within brackets, the words "one-half of the rate per kilometre notified by the concerned Director of Transport for auto-rickshaw" shall be substituted;
 - (ii) in clause (d), for the words, letters and figures "an allowance at the rate of Rs. 1.30 paise per kilometre", the words "road mileage allowance at the rate notified by the concerned Director of Transport" shall be substituted;
 - (iii) In clause (e),—
 - (a) for the letters and figures "Rs. 35", the letters and figures "Rs. 100" shall be substituted;

(b) in the second proviso,—

(i) for the existing para (i), the following para shall be substituted, namely :—

"(i) When a judge is required to perform functions outside his normal duties in localities away from his headquarters he may, subject to such conditions as the President may in each case determine be granted daily allowance not exceeding Rs. 100 per day for all type of localities and transport charges not exceeding Rs. 20/- per day in respect of specially expensive localities like Bombay, Calcutta, Madras, Delhi, Hyderabad, Ahmedabad, Bangalore or any other locality so declared hereafter by the President and shall also be entitled to Government accommodation at the same rates as for Government servants";

(ii) in para (ii), for the letters and figures "Rs. 42", the letters and figures "Rs. 100" shall be substituted;

(iii) in para (iii), for the letters and figures "Rs. 35", the letters and figures "Rs. 100" shall be substituted;

(3) in rule 6 for sub-rule (b), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(b) When travelling the road :—

- (i) one mileage allowance for the judge himself;
- (ii) one additional mileage allowance at the rate applicable to him, if two members of his family accompany him and at twice that rate if more than two members accompany him :

Provided that when any portion of the journey can be performed by railway, the allowance claimed in respect of that portion shall not exceed the amount admissible had the judge and the members of his family travelled on such portion by railway by the highest class including air-conditioned;"

(4) for rule 7-A, the following rule shall be substituted, namely :—

"7-A Notwithstanding anything contained in rule 5, a judge of the High Court shall be entitled to leave travel concession for himself, his wife and dependent members of his family for visiting any place in India (including permanent residence in his home state) during his leave, twice a year, in accordance with the rules applicable in this regard to a member of the Indian Administrative Service holding the

rank of Secretary to the Government of the State in which the principal seat of the High Court is situated.

Explanation :—for the purpose of this rule, 'leave' shall include vacation :

Provided that a judge of the Delhi High Court and a judge of the Punjab and Haryana High Court shall be entitled to leave travel concession under this rule, twice a year, for visiting a place anywhere in India (including home town in accordance with the rules applicable in this behalf to a member of the Indian Administrative Service holding the rank of a Joint Secretary to the Government of India;

Provided further that a Judge and his wife shall have the option to travel by air or by air-conditioned first class when travelling by railway, dependent members of the family shall also be allowed to travel with either of them by air or air-conditioned first class, when the judge or his wife travels on leave travel concession. Explanation-I : For the purpose of this rule and of rules 7-B and 7-C,—

"permanent residence in the home state" means (i) in the case of a person who has held a judicial office in the territory of India, such place as may have been recorded in his service records as the place at which his permanent residence is located, and (ii) in any other case, the place which has been declared by a judge of a High Court before the commencement of the High Court Judges (Travelling Allowance) Amendment Rules, 1966, as the place at which his permanent residence is located, or where no such declaration has been made, such place as the judge of a High Court may within one year from the commencement of the High Court Judges (Travelling Allowance) Amendment Rules, 1966 or from the date of his appointment, whichever is later, declare to be the place at which his permanent residence is located and the declaration so made shall not be changed unless the Central Government having regard to the exceptional circumstances of the case permits such change :

Provided that not more than one such change shall be permitted by the Central Government during the period of service of a judge of a High Court.

- II. "Year" means the 'Calendar Year', provided that in the event of the return journey falling in the succeeding calendar year, such journey shall be deemed to

have been performed in the year in which the outward journey had commenced;"

- (5) in rule 7-C, in sub-rule (1), in clause (b), for the existing sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely,—

"(i) one mileage allowance for one member of the family, a second mileage allowance if two members of the family travel and a third mileage allowance if more than two members of the family of the deceased judge travel, at the rate applicable to such judge on the date he was last on duty."

- (6) in rule 7-D, in sub-rule (b), for the existing clauses (i) and (ii), the following clause shall be substituted, namely :—

"one mileage allowance for the judge, a second mileage allowance if two members of the family travelling with him and a third mileage allowance if more than two members of his family travel with him, at the rate applicable to such judge on the date he was last on duty;"

- (7) rule 7-B and 7-E shall be omitted;

- (8) rule 7-C and 7-D shall be renumbered as 7B and 7-C respectively.

[F. No. 24/19/86-Jus.]

J. S. BADHAN, Jt. Secy.

Note :—Principal Rules published vide Notification No. S.R.O. 2401 dated 23rd October, 1956, Gazette of India dated 27th October, 1956, Part II, Section 3, page 1762.

Subsequently amended by :—

- (1) SRO 708 dated 28-2-1957
- (2) GSR 48 dated 9-1-1959
- (3) GSR 730 dated 4-5-1965
- (4) GSR 943 dated 8-6-1966
- (5) GSR 1768 dated 18-9-1968
- (6) GSR 891 dated 19-3-1969
- (7) GSR 784 dated 2-5-1970
- (8) GSR 1539 dated 4-9-1971
- (9) GSR 841 dated 21-6-1972
- (10) GSR 344(E) dated 12-5-1976
- (11) GSR 991 dated 28-7-1978
- (12) GSR 502 dated 23-3-1979
- (13) GSR 870 dated 5-8-1980
- (14) GSR 1044 dated 23-9-1980
- (15) GSR 360 dated 10-3-1981
- (16) GSR 532 dated 27-5-1982
- (17) GSR 887 dated 15-10-1982
- (18) GSR 1007 dated 2-11-1985.